

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2613
जिसका उत्तर 4 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।
13 अग्रहायण, 1941 (शक)

"डीपफेक" प्रौद्योगिकी

2613. सुश्री एस. जोतिमणि :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की "डीपफेक" प्रौद्योगिकी में हाल ही के विकास की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और
- (ख) विशेषकर झूठी खबर से निपटने के संबंध में प्रस्तावित राष्ट्रीय आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) : जी, हां। सरकार को "डीपफेक प्रौद्योगिकी" के बारे में पता है, जो आर्टिफिशिएल न्यूरल नेटवर्क तथा डीप लर्निंग/मशीन लर्निंग तकनीक का प्रयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की इमेज या वीडियो के साथ किसी व्यक्ति की इमेज या वीडियो मीडिया को परिवर्तित/सृजित करने में सक्षम बनाती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के जरिए फैलाई जा रही गलत सूचना और अफवाहों की ऐसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

(i) आईटी अधिनियम 2000 प्रावधानों के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आपत्तिजन सूचना सामग्री को हटाने के मुद्दे का प्रभावी समाधान करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ नियमित रूप से संपर्क में है।

(ii) मंत्रालय द्वारा दिए गए बल पर आधारित, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म पर झूठी खबरों जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए फोरवर्ड की संख्या सीमित करने तथा तथ्यों की जांच कराने को बढ़ावा देने के लिए जैसे पहले कार्यान्वित की है।

(iii) एमईआईटीवाई सूचना सुरक्षा शिक्षण और जागरूकता (आईएसईए) नामक एक कार्यक्रम के जरिए प्रयोक्ताओं में जागरूकता पैदा करता आ रहा है और अफवाहों/गलत समाचार को साझा न करने की सलाह दे रहा है। सूचना सुरक्षा जागरूकता के लिए एक समर्पित वेबसाइट <http://www.infosecawareness.in> सभी संगत जागरूकता सूचना सामग्री प्रदान करती है।

(iv) गृह मंत्रालय (एमएचए) ने साइबर सुरक्षा और साइबर संरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए "साइबर दोस्त" नामक ट्विटर हैंडल सृजित किया है। (एमएचए) ने साइबर सुरक्षा और वयस्कों/विद्यार्थियों के लिए एक हैंडबुक भी जारी की है।

(ख) : झूठी खबरों से निपटने के संबंध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना।
- नीतियों और कानूनों में अपेक्षित बदलाव सहित मानकों को तैयार करने तथा सुधारों को सक्षम बना करके नागरिकों को इसके लाभ उपलब्ध कराने के लिए एआई नवाचार, विकास, व्यापक स्तर पर प्रयोग और कार्यान्वयन को सुकर बनाना।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंधित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्षमताओं का निर्माण करना।
- भारतीय संदर्भ के लिए वैश्विक उत्कृष्ट अभ्यासों और सफल उपयोग के मामलों को सामने लाना।
- जनता के लिए जिम्मेदार एआई प्रविस्तावरण को बढ़ावा देना और सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना।

